

## खबर संक्षेप

## सेवा पखवाड़ा: जनसेवा का जनादोलन

सतना। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यशाला में 'सेवा पखवाड़ा' पर चर्चा की गई। यह पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) तक मनाया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि भाजपा की विचार धारा राष्ट्रहित और जनसेवा पर आधारित है, और यह पखवाड़ा केवल एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसेवा का जनादोलन है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नरेंद्र त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं से सम्पर्ण के साथ इसमें भाग लेने का आग्रह किया। जिला संयोजक ऋषभ सिंह ने कहा कि यह पखवाड़ा मोदी के नेतृत्व को समर्पित है और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना है। युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौभाग्य कंसरी ने कहा कि युवा कार्यकर्ता रक्तदान की कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं। इस कार्यशाला में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## मैहर जिले के नए पुलिस अधीक्षक बने अवधेश प्रताप सिंह, अगवाल का श्योपुर तबादला

मैहर। जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर बड़ा बदलाव हुआ है। अब अवधेश प्रताप सिंह को मैहर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वह इससे पहले बालाघाट में 36वीं वाहिनी विस्तार के सेनाजी के पद पर कार्यरत थे। वहीं मैहर के पहले पुलिस अधीक्षक सुधीर अगवाल का तबादला श्योपुर कर दिया गया है। मैहर जिले के गठन के बाद सुधीर अगवाल ने पहले एसपी के रूप में कार्यरत संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सख्त लेकिन संवेदनशील कार्यशैली के लिए लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ जनता के बीच विश्वास भी कायम किया। नशा मुक्ति अभियान, यातायात सुधार और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके काम की काफी सराहना हुई। हालांकि, तबादला एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन मैहर की जनता और पुलिस महकमे के लिए यह एक भावुक कर देने वाला क्षण है।

## 48 हजार रुपये की अवैध शराब जब्त

कटनी। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग ने आबकारी वृत्त क्रमांक 03 अंतर्गत ग्राम बिहपुरा, टेढ़ी, मानपुर एवं हरका टैंक में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ लाहव और हाथ भट्टी महिला ज्वेल की है। टीम ने दक्षिण के दौरान प्लास्टिक के गुब्बों में छिपाया गया 435 किलोग्राम महुआ लाहव और 30 लीटर हाथ भट्टी महिला ज्वेल की। ज्वेल की गई सामग्री की कुल अनुमानित कीमत लगभग 48 हजार रुपये आंकी गई है। टीम द्वारा नैके पर ही महुआ लाहव को जप्त कर दिया गया। इस मामले में, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क और च के तहत कुल 6 क्वॉटर दर्ज किए गए हैं।

## जिले में 72.14 फीसदी नागरिकों की समग्र ई-के.वाई.सी का कार्य पूर्ण

कटनी। शासन की हितवाही मूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितवाही को मिल सके इस हेतु कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशन एवं निगमायुक्त नीलेश दुबे के मार्गदर्शन में नगर में अभियान चलाकर पोर्टल में समग्र आई.डी.सी से आधार नंबर का काम आर्ड.डी.सी से आधार नंबर नीलेश दुबे द्वारा ई-के.वाई.सी कार्य की सतत समीक्षा की जाकर संलग्न गठित दल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-के.वाई.सी. कार्य में गति लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। निगमायुक्त नीलेश दुबे के निर्देशन में जिले में अब तक 72.14 फीसदी नागरिकों यानि 1 लाख 57 हजार 584 नागरिकों का समग्र आई.डी.सी से आधार से ई-के.वाई.सी कार्य किया जा चुका है। वहीं निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान के तहत सर्वे दल के वाई.डरोगा एवं वसुलीकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर नागरिकों की सतत आई.डी.सी का आधार से लिंक होने की जांच की जाकर शेष बचे नागरिकों का समग्र आई.डी.सी बनाई जा रही है।



## रीवा रोड और सिमरिया चौक पर ट्रैफिक की अराजकता जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं लोग

सतना। शहर में रीवा रोड बस स्टैंड और सिमरिया चौक के पास यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये दोनों ही क्षेत्र शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में गिने जाते हैं, जहां हर दिन हजारों लोग आते-जाते हैं। लेकिन यहां व्याप्त अराजकता ने न केवल यात्रियों को, बल्कि स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भी भारी परेशानी में डाल दिया है। सड़कों पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और बीच रास्ते में सवारियों भरते ऑटो-बस चालकों की मनमानी के कारण यहां हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है।

## ऑटो-बसों की मनमानी से

## चरमराती व्यवस्था

रीवा रोड बस स्टैंड और सिमरिया चौक पर ऑटो और बस चालकों की दादागिरी चरम पर है। यात्री सुविधा के लिए बने स्टैंड को छोड़कर ये चालक



अपनी गाड़ियां सड़क के बीचों-बीच खड़ी कर देते हैं। इससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इन चालकों को न तो ट्रैफिक नियमों की परवाह है और न ही

राहगीरों की सुरक्षा की। वे सवारी भरने के चक्कर में अक्सर एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं, जिससे कई बार छोटी-मोटी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

## आम जनता की बड़ी मुश्किलें

इस अव्यवस्थित यातायात का सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और बाजार आने वाले लोगों को रोज इस जाम से जूझना पड़ता है। पैदल चलने वालों के लिए तो स्थिति और भी खराब है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के कारण उन्हें फुटपाथ का उपयोग करने का मौका नहीं मिलता और वे मजबूरन सड़क पर चलने को मजबूर होते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है।

## ट्रैफिक पुलिस की 'लापता'

## मौजूदगी

चौकाने वाली बात यह है कि यातायात की इस गंभीर समस्या पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी ने क बराबर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की

अनदेखी और लापरवाही के कारण ही ऑटो-बस चालकों के होसले बुलंद हैं। अगर यहां नियमित रूप से पुलिसकर्मी तैनात रहें और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें, तो हालात में काफी सुधार हो सकता है। लोगों ने कई बार इस बारे में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

## प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग

इस समस्या से परेशान लोगों ने अब प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो यह अराजकता और बढ़ेगी, जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह समय की मांग है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें और शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाएं, ताकि लोग सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें।

## राशन दुकान संचालक की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत

सतना। राशन दुकान के संचालक की मनमानी से तंग आकर सतना जिले की उचेहरा तहसील के बांधी मोहार और बंधवा टोला के लगभग दो दर्जन ग्रामीण मंगलवार को सतना कलेक्टर पहुंचे। उन्होंने जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान संचालक दो महीने में केवल एक महीने का ही राशन देता है, जबकि उसने दो बार फिंगरप्रिंट लेकर दो महीने का अनाज निकाल लिया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि केवाईसी अपडेट करने के नाम पर उनसे 30 से 50 रुपये तक लिए गए हैं। शिकायत करने आए ग्रामीण हीरालाल कोल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो उनका राशन बंद कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे कलेक्टर में शिकायत कर रहे थे, तो राशन दुकान संचालक का फोन आया और उसने उन्हें धमकी दी। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर ने मौके पर ही जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को मामले की जांच करने और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इस मामले में आगे की कार्रवाई होने की उम्मीद है ताकि जरूरतमंदों को उनका पूरा हक मिल सके। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर करती है।

## पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की कई फर्जी सिम कार्ड सहित डेबिट कार्ड एवं चेक बुक किया जब्त

## फर्जी सिमों से लाखों की गड़बड़ी, दो और गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज | स्लीमनाबाद

फर्जी सिम एक्टिवेट कर बेचने वाले गिरोह के दो और सदस्यों को बहोरीबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा संदिग्ध (POS) सिम विक्रयकर्ता एजेन्टों, धारकों के विरुद्ध आपरेशन फास्ट के तहत कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन में बहोरीबंद पुलिस ने विगत दिनों आधारकार्ड, फोटो एवं अगुटे का प्रिन्ट लेकर फर्जी सिम एक्टिवेट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। रात 04 सितंबर को मूरत सिंह निझरौली की रिपोर्ट पर आरोपी जितेन्द्र बर्मन निवासी पाकर के विरुद्ध धारा 318(4) BNS एवं धारा 66 C.I.T. ACT का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान टेली कम्यूनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 42(3) (B) और आधार एक्ट 2016 की धारा 47, 48 का गठन होना पाये जाने से धाराओं का इजाफा किया गया। जांच में फर्जी सिम एक्टिवेट कर लाखों रुपए की गड़बड़ी करने के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है।



इस मामले में बहोरीबंद पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया व एसडीओपी स्लीमनाबाद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोरीबंद निरीक्षक अखलेश दाहिया विसर टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी (pos) सिम विक्रयकर्ता एजेन्ट जितेन्द्र बर्मन को गिरफ्तारी की गयी। पकड़ा गया सिम विक्रयकर्ता एजेन्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते खोलना, एयरटेल से जियो और जियो से एयरटेल में सिमों को पोर्ट करने का काम करता था। इसी दौरान मूरत सिंह ग्राम झरौली के खाता खुलवाने आने पर एवं आनंद कुमार चौधरी के मोबाइल नंबर को

एयरटेल से जियो में पोर्ट कराने आने पर उनका आधार कार्ड नंबर व फोटो लेकर एयरटेल कंपनी की सिम को धोधाघड़ी बेईमानी पूर्वक फर्जी सिम एक्टिवेट कर ग्राम अमाडी के अब्राहम खान, सलमान खान, मुस्तकीम खान और मसंधा के संदीप लोधी (पटेल) से 500, 500 रुपये लेकर बेच दी थीं। जिन फर्जी सिम नम्बरो से लाखों रुपये का सायबर फ्राड किया गया है।

## आरोपितों से ये सामग्री जब्त

आरोपी जितेन्द्र बर्मन का साथी सिम विक्रयकर्ता आदर्श चौधरी नि. पटीराजा (एयरटेल - FSC) भी आरोपी के साथ मिलकर लोगों के आधार और फोटो से फर्जी सिम एक्टिवेट कर

जांच की गई। किट में 5 का एक पैकेट मूंग दाल, एक बिस्कुट का पैकेट, एक भुजिया नमकीन का पैकेट, एक पानी का पाउच और दो केले दिए गए थे। इन सभी सामानों की कुल कीमत 20 के आसपास ही है, जबकि सरकार ने इसके लिए 50 का बजट तय किया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले, 25 अगस्त को मैहर में भी इसी तरह की शिकायत सामने आई थी, जहाँ महिलाओं को 50 के बजट में सिर्फ 15 का सामान दिया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला है। इस पूरे मामले में विभागीय जिम्मेदार, कथित तौर पर पंकज नाम के व्यक्ति की राजनीति के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। इस गंभीर शिकायत को संज्ञान में लिया गया है। संबंधित विभाग के एक

अधिकारी ने बताया, जिस एजेंसी द्वारा यह गड़बड़ी की जा रही है, इस महीने से उसके कार्य आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब से यह कार्य खंड चिकित्सा अधिकारी स्वयं अपने स्तर से करेंगे और स्थानीय एजेंसियों से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जो भी गड़बड़ियां की गई हैं, उनके लॉबि बिलों पर आर्थिक दंड लगाकर वसूली की जाएगी। यह भ्रष्टाचार न केवल सरकारी योजना की विफलता को दर्शाता है, बल्कि सीधे तौर पर गंभवती महिलाओं के 'सुरक्षित मातृत्व के अधिकार' पर भी चोट है। अधिकारियों की इस पर चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है और यह उजागर करती है कि कैसे गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है।

## 'सुरक्षित मातृत्व अभियान' में घोटाला: गर्भवती महिलाओं को दिए जा रहे 50 के बजाय 20 के पोषण किट

सतना। जिले में चल रहे 'सुरक्षित मातृत्व अभियान' में एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में भारी गड़बड़ी पाई गई है। महिलाओं को 50 की निर्धारित राशि के बजाय, केवल 20 मूल्य का पोषण किट थमाया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है।

यह मामला तब सामने आया जब रामनगर अस्पताल में वितरित किए गए पोषण किट की

जांच की गई। किट में 5 का एक पैकेट मूंग दाल, एक बिस्कुट का पैकेट, एक भुजिया नमकीन का पैकेट, एक पानी का पाउच और दो केले दिए गए थे। इन सभी सामानों की कुल कीमत 20 के आसपास ही है, जबकि सरकार ने इसके लिए 50 का बजट तय किया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले, 25 अगस्त को मैहर में भी इसी तरह की शिकायत सामने आई थी, जहाँ महिलाओं को 50 के बजट में सिर्फ 15 का सामान दिया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला है। इस पूरे मामले में विभागीय जिम्मेदार, कथित तौर पर पंकज नाम के व्यक्ति की राजनीति के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। इस गंभीर शिकायत को संज्ञान में लिया गया है। संबंधित विभाग के एक

अधिकारी ने बताया, जिस एजेंसी द्वारा यह गड़बड़ी की जा रही है, इस महीने से उसके कार्य आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब से यह कार्य खंड चिकित्सा अधिकारी स्वयं अपने स्तर से करेंगे और स्थानीय एजेंसियों से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जो भी गड़बड़ियां की गई हैं, उनके लॉबि बिलों पर आर्थिक दंड लगाकर वसूली की जाएगी। यह भ्रष्टाचार न केवल सरकारी योजना की विफलता को दर्शाता है, बल्कि सीधे तौर पर गंभवती महिलाओं के 'सुरक्षित मातृत्व के अधिकार' पर भी चोट है। अधिकारियों की इस पर चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है और यह उजागर करती है कि कैसे गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है।

## मैहर में पानी से भरे खदान में मिला युवक का शव, मिर्गी के दौर की आशंका

मैहर। जिले के नादन देहात थाना क्षेत्र के ग्राम खरौंदी में पानी से भरी एक खुली खदान में 33 वर्षीय युवक मिथुन कोल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को पानी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। नादन देहात थाना प्रभारी के.एन.बंजारे ने बताया कि मिथुन मजदूरी का काम करता था और सोमवार शाम मजदूरी करके घर लौट रहा था। रास्ते में खदान के पास वह शौच के लिए रुका, जबकि उसके साथी आगे निकल गए। जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। खदान के पास उसके कपड़े मिले, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से पानी में तलाश की गई। थोड़ी देर बाद उसका शव बरामद हो गया। लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक मिथुन को मिर्गी की बीमारी थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसे खदान के पास मिर्गी का दौरा पड़ा होगा, जिससे वह पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मैहर सिविल अस्पताल भेजा, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता रामानंद पटेल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की।





**खबर संक्षेप**

**अपर कलेक्टर विकास ने 70 आवेदन पत्रों में की सुनवाई**

रीवा। कलेक्टर के मोहन सभागर में आमजनता के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर विकास मेहताब सिंह गुर्जर ने आमजनता के 70 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर आरके सिन्हा तथा डिप्टी कलेक्टर जीपी अग्रवाल ने भी आमजनता के आवेदनों में सुनवाई की। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर आरके सिन्हा तथा डिप्टी कलेक्टर जीपी अग्रवाल ने भी आमजनता के आवेदनों में सुनवाई की। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

**बिना जवाबदेही तय किए, पीडब्ल्यूडी और अस्पताल प्रशासन एक-दूसरे पर टाल रहे जिम्मेदारी**

# सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की इमारत संकट में, 5 साल में ही फटा पिलर

रीवा। प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित स्वास्थ्य अधोसंरचना पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रीवा स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की हालत महज पांच वर्षों में ही जर्जर होती नजर आ रही है। अस्पताल के एक प्रमुख पिलर में दरार आने और दीवार के क्षतिग्रस्त होने की घटना ने भवन निर्माण की गुणवत्ता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। बताया जा रहा है कि यह दरार एक लंबे समय से देखी जा रही थी, लेकिन उसे समय रहते मरम्मत नहीं करवाया गया। अब स्थिति यह है कि दरारें बढ़ती जा रही हैं और पिलर के पास के हिस्से में संरचनात्मक क्षति गंभीर रूप ले चुकी है। इस खबर के सामने आते ही अस्पताल प्रशासन और लोक निर्माण विभाग में अफरातफरी मच गई। इस अस्पताल की नींव अगस्त 2016 में रखी गई थी और इसका लोकार्पण 7 अक्टूबर 2020 को किया गया था। मात्र पांच वर्षों में ही भवन के इस हाल ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े

कर दिए हैं। जिस स्थान पर दरार आई है, वह मुख्य पिलर के समीप है यानि भवन की संरचनात्मक मजबूती पर ही अब संदेह हो गया है स्थानीय समाजसेवियों का कहना है कि जिस इमारत में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, उसकी यह दशा प्रदेश की निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल है। अब मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

**फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं**

**आम, कई मरीज घायल**  
केवल पिलर में दरार ही नहीं, अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में न्यूरोलॉजी विभाग में छत की फॉल सीलिंग गिरने से कई मरीज घायल हो गए थे। इससे पहले आउटडोर विभाग में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह



है कि इन घटनाओं के बाद अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

**कागजी कार्रवाई में उलझा सच, जमीन पर कोई टोस कदम नहीं**  
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को सूचना दे दी है और विभाग द्वारा

तकनीकी जांच की जा रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण की जिम्मेदारी उस समय के ठेकेदार और तत्कालीन इंजीनियरों की थी। यानी जवाबदेही तय करने के बजाय जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाली जा रही है। हर समय मौजूद रहते हैं सैकड़ों मरीज और स्टाफ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज होता है। दिन-रात मरीज, उनके परिजन और मेडिकल स्टाफ यहां मौजूद रहते हैं। ऐसे में भवन की खस्ताहाल स्थिति किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

**मानक के विपरीत निर्माण कार्य कराया गया**

सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट वीके माला ने पूरे मामले पर कहा कि जनता के साथ धोखा हर महीने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा की कभी छत की सीलिंग गिरती है तो कभी आधा निर्माण

भाग ही निकल जाता है इस प्रकार की लगातार घटनाएं सुपर स्पेशलिटी में हो रही है उसका मूल कारण है मानक के विपरीत निर्माण कार्य कराए गए व्यक्तिगत श्रेय लेने के उद्देश्य जल्दबाजी में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया जो मानक मापदंडों के पूर्णता विपरीत साथी गुणवत्ता विहीन निर्माण कर कराया गया इस कर में लगे हुए तकनीकी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए निर्माण एजेंसी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ विषय स्वास्थ्य हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में कोई बड़ी अपनी घटनाएं घटित हो सकते हैं इसकी आखिर जवाबदारी किसकी होगी साथ ही सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक डॉ श्रीवास्तव के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन सब कमियों को लेकर समय पर रहते हुए अपने सजक नहीं किया और जानकारी नहीं दी इस पूरे व्यापक भ्रष्टाचार कमीशन खोरी के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।

## नोटरी महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

रीवा। नोटरी महासंघ रीवा द्वारा नोटेरियल शुल्क में वृद्धि को लेकर राष्ट्रपति के नाम से आयुक्त रीवा संभाग को ज्ञापन सौंप कर नोटेरियल शुल्क वृद्धि किए जाने की मांग की है नोटरी महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा स्टॉप शुल्क में भारी वृद्धि की गई है जो शायद पत्र ₹50 के स्टॉप में दिया जाता था उसे ₹200 कर दिया गया है हर नोटेरियल कार्य में लगाए जाने वाले स्टॉप में व्यापक वृद्धि की गई है परंतु नोटरी कार्य के शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए नोटेरियल शुल्क में वृद्धि किया जाना आवश्यक है उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्रदेशसरकार के द्वारा बढ़ाये गए शुल्क के अनुरूप नोटरीयों द्वारा कोई भी दस्तावेज स्टॉपित किया जाए और कमिश्नर महोदय से उन्होंने सभी विभागों को स्टॉप वृद्धि के अनुरूप ही स्टॉपित दस्तावेज लेने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है उन्होंने बताया कि अभी भी

कई शासकीय विभाग ₹10 और ₹50 के स्टॉप को ले रहे हैं जिस पर रोक लगाई जाए और सभी शासकीय विभाग नए आदेश के अनुरूप ही स्टॉप प्राप्त करें राज सरकार के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रीवा जिले में स्टॉप के माध्यम से राजस्व को क्षति पहुंचाने का खेल हो रहा है जिस पर प्रशासनिक अधिकारी औचक निरीक्षण कर दस्तावेज का सत्यापन करें किरायानामा अनिवार्य किया जाए और मकान मालिकों को अनिवार्य रूप से किराया नाम बनवाकर उसका सत्यापन बढ़े हुए स्टॉप के अनुरूप किया जाए जिससे राज्य सरकार को राजस्व की क्षतिपूर्ति ना हो ज्ञापन के माध्यम से नोटेरियल टिकट ₹50 की छपाईका आग्रह भी किया गया है ज्ञापन देने वाले दल में नोटरी महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तिवारी संयोजक योगेंद्र शुक्ला महामंत्री अनिल कुमार श्रीवास्तव और मनोज सिंह सिंगर सहित नोटरी गण उपस्थित रहे।

## रोजगार मेले के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तैयारी करें - कमिश्नर

**संभागीय बैठक के निर्देशों पर तथ्यपूर्ण रिपोर्ट दें**

रीवा। कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री तथा प्रभारी अपर मुख्य सचिव द्वारा ली गई संभागीय बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभागीय बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों और दिए गए सुझावों के संबंध में विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करें। जो बिन्दु शासन स्तर से संबंधित हैं उनके प्रस्ताव भेजकर लगातार फालोअप करें। बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन में सभी अधिकारी तथ्यपूर्ण जानकारी दर्ज करें। जिला और संभाग स्तर की कोई भी कार्यवाही लंबित न रहे। सभी अधिकारी पालन प्रतिवेदन में अद्यतन जानकारी पोर्टल पर आज ही अपडेट कर दें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि 17 सितम्बर को संभाग की प्रभारी अपर मुख्य सचिव संभागीय बैठक के निर्देशों की समीक्षा करेंगे। बैठक से पूर्व सभी अधिकारी विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। बैठक में कमिश्नर ने गोड सागर सिंचाई परियोजना, सिंगरोली में स्टेडियम निर्माण, मेहर-उमरिया मार्ग में महानदी पुल के सुधार कार्य, त्योंथर फ्लो सिंचाई



परियोजना तथा दौरी सागर बांध निर्माण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में गौ वन्य विहार अभ्यारण्य निर्माण के प्रस्ताव एक सप्ताह में प्रस्तुत कर दें। मेहर में माँ शारदा लोक निर्माण की व्यावहारिक कार्ययोजना बनाकर शासन द्वारा आवंटित राशि से निर्माण प्रस्तावित करें। चित्रकूट में भी वनवासी रामलोक निर्माण की कार्ययोजना में आवश्यक सुधार करके उसे पुनः प्रस्तुत करें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में वृहद रोजगार मेले में 50 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रकरण स्वीकृत करारक हितग्राहियों को रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित करें। सीएम हेल्पलाइन के

लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रतिदिन एक आवेदक से फोन से संपर्क करें। समाधान ऑनलाइन के एजेंडा बिन्दुओं पर लंबित प्रकरणों तथा 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। सभी अधिकारी ई ऑफिस के माध्यम से ही पत्राचार करें तथा फाइलें भेजें। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास शशि श्याम उदके, चीफ इंजीनियर ऊर्जा प्रभा पाण्डेय, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, अधीक्षण यंत्रि पीएचई महेंद्र सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

## डीआईजी राजेश सिंह भोपाल स्थानांतरित, हेमंत चौहान को सौंपी गई रीवा रेंज की कमान

रीवा। मुख्यमंत्री के मऊगंज दौरे के ठीक 24 घंटे के भीतर आईपीएस स्तर पर फेरबदल किया गया, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डीआईजी राजेश सिंह चंदेला का तबादला कर उन्हें भोपाल ग्रामीण रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत चौहान को रीवा रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है। हेमंत चौहान इससे पहले कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें मुठुभाषी एवं सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है, उल्लेखनीय है कि राजेश सिंह चंदेला को मात्र छह माह पूर्व ही डीआईजी रीवा रेंज की जिम्मेदारी दी गई थी।

रीवा। मुख्यमंत्री के मऊगंज दौरे के ठीक 24 घंटे के भीतर आईपीएस स्तर पर फेरबदल किया गया, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डीआईजी राजेश सिंह चंदेला का तबादला कर उन्हें भोपाल ग्रामीण रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत चौहान को रीवा रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है। हेमंत चौहान इससे पहले कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें मुठुभाषी एवं सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है, उल्लेखनीय है कि राजेश सिंह चंदेला को मात्र छह माह पूर्व ही डीआईजी रीवा रेंज की जिम्मेदारी दी गई थी।

**शैलेंद्र सिंह चौहान बने रीवा नवागत पुलिस अधीक्षक**

रीवा। जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का तबादला कर दिया गया है। वे अब नई पदस्थापना के तहत भोपाल में सेवाएं देंगे। उनकी जगह शैलेंद्र सिंह चौहान को रीवा जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। शासन द्वारा जारी तबादला आदेश के मुताबिक, शैलेंद्र सिंह चौहान जल्द ही रीवा में कार्यभार ग्रहण करेंगे। विवेक सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को तत्कालीन एसपी नवनीत भसीन से रीवा का चार्ज लिया था और अपने 2 साल 7 महीने के कार्यकाल में जिले की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कीं। अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम रोकथाम, ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस-पब्लिक संवाद जैसे विषयों पर उन्होंने गंभीरता से कार्य किया। शैलेंद्र सिंह चौहान का अनुभव जिले के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है नए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के पास व्यापक प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था का अनुभव है। वे इससे पहले भिंड और मुरैना जैसे संवेदनशील जिलों में बतौर एसपी सेवा दे चुके हैं। 29 अप्रैल 2023 को उन्हें भिंड में प्रशासनांतरित कर मुरैना का एसपी बनाया गया था। इसके बाद 10 अगस्त 2024 को उन्हें ग्वालियर में एसएफए 13वीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया। चौहान के रीवा आने से कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।



## कमिश्नर और अन्य अधिकारी साइकिल से पहुंचे कार्यालय

रीवा। पर्यावरण की सुरक्षा तथा स्वयं की स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य से सप्ताह में मंगलवार के दिन कमिश्नर बीएस जामोद की पहल पर अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं। यह क्रम लगातार बना हुआ है। सुमंगल साइकिल दिवस पर कमिश्नर और अन्य अधिकारी साइकिल से कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। कमिश्नर के साथ संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल



गुप्ता, उप संचालक खनिज बसंतराम, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरोपी सिंह, अधीक्षण यंत्रि पीएचई महेंद्र सिंह, संयुक्त संचालक पेंशन तथा कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारी भी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। जिला संचालक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब गुर्जर ई रिक्शा से कार्यालय पहुंचे। इसी तरह अन्य अधिकारियों ने भी कार्यालय पहुंचने के लिए साइकिल और ई रिक्शों का उपयोग किया।

## 5.21 करोड़ में तय हुआ अटल पार्क का टेका

रीवा। शहर के सिरमौर चौराहा स्थित अटल पार्क में प्रवेश के लिए अब शुल्क देना होगा इसकी व्यवस्था नगर निगम ने कर दी है। इस बात को सोमवार को निविदा कार्रवाई पूरी हो गई। आरध्या श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटर शशवर्धन सिंह को प्रवेश शुल्क वसूली का टेका दिया गया है। नगर निगम ने उक्त एजेंसी को 5.21 करोड़ की बोली लगाने पर टेका दिया। राशि जमा होने के बाद अगले 5 साल तक उक्त टेका एजेंसी अटल पार्क में शुल्क वसूली का काम करेगी। इसमें पार्क के साथ ही फूड प्लाजा कॉम्प्लेक्स और पार्किंग परिया भी शामिल है। नगर निगम प्रशासन की

निविदा शर्तों के तहत सुबह 5 से 8 बजे तक आम और खास लोगों के रैर-सपाट को शुल्क मुक्त रखा गया है। इस नीलामी में 8 फर्में ने भाग लिया था। गौरतलब है कि अभी तक शहर के आम और खास इस पार्क में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने जाया करते थे, लेकिन अब इवनिंग वॉक नहीं कर पाएंगे। बताया गया कि निगम ने जब टेंडर मंगाए थे, तब बेस वैल्यू 1.16 करोड़ रुपये थी। फिर बीते 4 सितंबर को निगम ने टेंडर 1.83 करोड़ के बेस वैल्यू पर खोला, जिसकी वैल्यू बढ़कर 2.89 करोड़ तक पहुंची। इसके बाद निगम प्रशासन ने ओपेन टेंडर चालू कर दिया। लिहाजा

**रीवा के कंपनी को मिली जिम्मेदारी**



टेंडर लेने टेका एजेंसी ऊंची बोली लगाने लगी। आखिरकार सोमवार को 5.21 करोड़ रुपये में आरध्या एजेंसी के नाम टेंडर फाइनल हो गया। इन्होंने लगाई बोली एजेंसी बोली रकम आरध्या श्रीराम प्रा.लि. (विजेता) 5.21 करोड़

## ऋषिराज कुलम विद्यालय में एचआईवी एड्स जनजागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित



मऊगंज। मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलने वाले सघन जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत ऋषिराज कुलम मऊगंज में एचआईवी/एड्स जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को एसएसके मैनेजर पुष्पराज विश्वकर्मा ने एचआईवी/एड्स एवं यौन संचारित रोगों के फैलने के कारणों और उनके बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही टीबी और वर्ष 2017 एचए के संबंध में विस्तार से बताया। विद्यार्थियों को अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1097 के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर विकास सिंह, प्राचार्य, एसएसके मैनेजर पुष्पराज विश्वकर्मा, एसएसके ओआरडब्ल्यू लवकुश वर्मा, एसएसके ओआरडब्ल्यू जैनेंद्र श्रीवास्तव, समाजसेवी रामरतन मिश्रा, सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया।

## मऊगंज में नगर परिषद द्वारा गौवंश को सुरक्षित जगह पहुंचाने का कार्य जारी

मऊगंज। कलेक्टर संजय कुमार जैन द्वारा आवारा गौवंश को गौशाला में पहुंचाने का आदेश नगर परिषद और जनपद पंचायत को जारी किया था जिसके अनुसार समस्त कर्मचारीगण नगर परिषद के कर्मचारी और ग्राम पंचायत के सचिवों को भी आदेश दिए थे कि अगर सड़क में एक भी आवारा गौवंश देखे गए तो सम्बन्धित कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी आज नगर परिषद के सब इंजीनियर अविनाश पटेल सफाई दरोगा प्रभारी अशीष पटेल नल जल योजना के देखने वाले बृजेंद्र गौतम वहीं सफाई दरोगा मनोज गुप्ता लकी मैत्रे के साथ सफाई कर्मी गौवंश को सुबह से ही सुरक्षित स्थान गौशाला पहुंचाने का जोरदार प्रयास करते हुए देखे गए मऊगंज नगर परिषद अध्यक्ष बुजवासी पटेल उनके साथ



सीएमओ द्वारा प्रयास किया गया हर गांव के लोग देखने को मिला की पशुओं का जीवन के साथ एवं किसान जिला कलेक्टर महोदय को बधाई देते हुए उत्साह भरी बोले की यह दिन आज

देखने को मिला की पशुओं का जीवन के साथ किसानों का जीवन मेहनत पर सोचने वाले जिला कलेक्टर ने पहल किया है।